

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या 13/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांक: 11.1.2018
अन्तर्गत धारा: 76 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

हरि प्रसाद आत्मज कूका जाति रेबारी निवासी शिवनगर ढाणी, तहसील खानपुर जिला झालावाड-राज०।
...अपीलाट

बनाम

- 1 इन्द्राबाई पत्नी स्व० दौलतराम जाति रेबारी निवासी हाल शिवनगर ढाणी तहसील खानपुर जिला झालावाड।
- 2 ग्राम पंचायत शिवनगर ढाणी, तहसील खानपुर जिला झालावाड।
- 3 तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बृजराज कुमार मंत्री अभिभाषक अपीलाट
श्री रूपेश कुमार श्रृंगी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम-1



निर्णय

दिनांक 31.7.2018


अपीलार्थी हरिप्रसाद ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं० 56/17/अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान इन्द्राबाई बनाम हरिप्रसाद वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि इन्द्राबाई रेस्पो० क्रम-1 ने नायब तहसीलदार सारोला कंला द्वारा वसीयत के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं० 541 दिनांक 11.2.2017 ग्राम शिवनगर ढाणी से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि उसके पति स्व० दौलतराम को हरिप्रसाद ने वृद्धवस्था की पेंशन चालू करवाने का बहाना बनाकर उप पंजीयक कार्यालय मे ले जाकर विवादित आराजी कुल 11 किता रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा तथा ख० नं० 120 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा मे अपने सम्पूर्ण हिस्से की झूठी वसीयत करवाली जिसके अनुसार उक्त नामा० खोला गया है जो नियम विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 13.10.2017 को अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकरण सं० 541 ग्राम शिवनगरढाणी निरस्त कर प्रकरण

बति० सं० आद०
कोटा

तथ्यात्मक जांच कर पुनः निर्णय पारित करने की कार्यवाही नियमानुसार करने हेतु नायब तहसीलदार सारोलाकंला को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांत हरिप्रसाद द्वारा धारा 76 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा में इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय में मान्यता प्राप्त संचिका के सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि नामा० सं० 541 रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसका बनावटी एवं कूटरचित होने का किसी प्रकार कोई प्रश्न नहीं होता दौलतराम ने अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांत के पक्ष में आलेखित की थी जो गवाहों से प्रमाणित एवं उप पंजीयक कार्यालय द्वारा तस्दीक की गई है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा इन्तकाल सही तस्दीक किया गया है। कानूनन किसी भी व्यक्ति को अपने हिस्से की वसीयत करने का कानूनी रूप से पूर्ण अधिकार प्राप्त है इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांत के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.12.2017 को बताने पर हुई। देरी क्षम्य हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रा० पत्र के साथ अपील पेश है। अतः विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.10.2017 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नामान्तरकरण सं० 541 नायब तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार तस्दीक किया गया है। कानूनन किसी भी व्यक्ति को अपने हिस्से की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार है। राजस्व न्यायालय को वसीयत की जांच करने का अधिकार नहीं है। रेस्पो० ने वसीयत को सिविल कोर्ट में चलेन्ज किया हुआ है जिसमें निर्णय हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया। बहस में आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी विवादित नामा० की नकल 7.3.2017 को जारी हुई है अपील दिनांक 6.6.2017 को पेश की गई है। विलम्ब के संबध में किया गया कथन न्यायोचित नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बिन्दू को कन्सीडर कर नामा० निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांड करने में त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2006-07 पेज 59 का न्यायिक उद्धरण पेश कर अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।
- 4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो० क्रम-1 ने बहस में बताया कि दौलतराम रेस्पो० क्रम-1 का पति है जिसके कोई संतान नहीं है। हरिप्रसाद ने दौलतराम को बहकावे में लेकर अपने पक्ष में कूटरचित वसीयत दिनांक 19.8.2015 को निष्पादित करवाली जिसके आधार पर ना० तहसीलदार सारोला द्वारा नामा० सं० 541 तस्दीक किया गया। नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व दौलतराम की पत्नी को नोटिस व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। वसीयत को गवाहान से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। वसीयत को प्रमाणित नहीं करवाया गया। मैंने वसीयत को सिविल कोर्ट में चलेन्ज किया है। उक्त इन्तकाल रेस्पो० इन्द्राबाई पत्नि दौलतराम की अनुपस्थिति में तस्दीक किया गया। जानकारी की तिथी से अधीनस्थ न्यायालय में अपील अवधि मध्य पेश की थी डिले कन्डोन हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था। अपने तर्क के समर्थन में आरआरटी 2009 (1) पेज 685 का न्यायिक उद्धरण पेश कर अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।
- 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपील पत्रावली तथा प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांत द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः प्रकरण का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।


वित्त. सं. भा. ३
जे. ३

अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ डिले कन्डोन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर जानकारी की तिथी 18.12.2017 से अपील को अवधि मध्य होना वर्णित किया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ में वर्णित तथ्यों के खण्डन में रेस्पोंडेंट क्रम-1 द्वारा कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं किया है। अतः शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रवली में कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित में क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

- 6 जेरअपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 13.10.17 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सं० 2070 के अवलोकन से विवादित आराजी मृतक दौलतराम की पुश्तैनी आराजी होना प्रकट होता है। विवादित आराजी मृतक दौलतराम की पुश्तैनी थी स्वयं द्वारा अर्जित नहीं की थी। ऐसी स्थिति में वसीयत करने करने का उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था प्रथम अपीलीय न्यायालय का उक्त अभिमत विधिसम्मत होना प्रकट होता है। अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट क्रम-1 के मध्य मुख्यतया विवाद मृतक दौलतराम द्वारा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत को लेकर है जिसके आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा नामा० सं० 541 तस्दीक किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भूमि मृतक दौलतराम की स्वअर्जित नहीं होकर पुश्तैनी होने से वसीयत करने का दौलतराम को अधिकार नहीं होना मानते हुये रेस्पोंडेंट क्रम-1 इन्द्राबाई द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार कर नामा० सं० 541 को निरस्त कर प्रकरण में तथ्यात्मक जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण में रेस्पोंडेंट क्रम-1 इन्द्राबाई द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के साथ दस्तावेजात, प्रमाणित प्रति कार्यवाही धारा 107, 151 सीआरपीसी सरकार बनाम हरिप्रसाद दिनांक 9.6.17, प्रमाणित प्रतिलिपी शिकायत दिनांक 20.5.2017 पुलिस अधीक्षक झालावाड, प्रमाणित प्रतिलिपी वाद पत्र एवं आदेशिका न्यायालय सिविल न्यायाधीश क० ख० खानपुर जिला झालावाड पेश की गई जो अपील प्रकरण के निर्णय में सहायक होने से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते हैं। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपी वाद पत्र एवं आदेशिका न्यायालय सिविल न्यायाधीश क० ख० खानपुर जिला झालावाड के अवलोकन से रेस्पोंडेंट क्रम-1 इन्द्राबाई द्वारा वसीयत को सिविल न्यायालय में चलेन्ज किये जाने की पुष्टि होती है ऐसी स्थिति में पक्षकारान के हितों का निर्धारण उक्त वाद प्रकरण में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है। नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में पक्षकारों के स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जाता है अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत अपील प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण चस्प्या नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।
- 7 निर्णय आज दिनांक 31.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गौस्वामी)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा